

कार्य कराने में तीन हजार 370 करोड़ रुपए किया जाएगा खर्च

कोल इंडिया कराएगा 21 रेलवे साइडिंग का निर्माण

हरिभूमि न्यूज ✎ कोरबा

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा अपनी चार अनुषंगी इकाइयों में 3 हजार 370 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 21 रेलवे साइडिंग का निर्माण कर रही है। इन रेलवे साइडिंग के वित्त वर्ष 2023-24 तक पूरा होने की उम्मीद है। रेलवे साइडिंग वह क्षेत्र है जिसका उपयोग कोयले को रेलवे रैक में लदान और उतारने के लिए किया जाता है। कोल इंडिया के पास फिलहाल 152 रेल साइडिंग हैं और 2024 तक इनकी संख्या 173 हो



फाइल फोटो

जाने का अनुमान है।

कोल इंडिया कोयले के परिचालन को लेकर स्वच्छ

वातावरण पर जोर दे रही है। इसके तहत रेलगाड़ी के जरिए कोयले के परिवहन के लिये रेल नेटवर्क को

बढ़ावा दे रही है। कंपनी धीरे-धीरे कोयला दुलाई का काम सड़क मार्ग से करने की बजाय रेलवे से ही करने पर जोर देगी। कोयले की दुलाई सड़क मार्ग से नहीं होने से धूलकण उड़ने के कारण होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगेगा और डीजल पर होने वाला खर्च बचेगा। चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक कोल इंडिया का रेलवे के जरिये कोयला दुलाई करीब 20.2 करोड़ टन रहा जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक है। वहीं सड़क मार्ग से दुलाई 33 प्रतिशत कम हुई है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भी कोयले की सड़क मार्ग से दुलाई 11

प्रतिशत कम रही है। कोल इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, रेल साइडिंग से कोयले की प्रभावी तरीके से निकासी सुनिश्चित होगी और कोल इंडिया के अंतिम छोर तक कोयला पहुंचाने के प्रयासों को गति मिलेगी। कोल इंडिया द्वारा अपने तीन अनुषंगी कंपनियों में 21 नए रेलवे साइडिंग का निर्माण किया जाएगा। इन अनुषंगी कंपनियों में एसईसीएल भी शामिल है। एसईसीएल में कुल 13 नए रेलवे साइडिंग का निर्माण किया जाएगा। जिले में एसईसीएल के कुसमुंडा व दीपका परियोजना में भी दो नए रेलवे साइडिंग ✎ शेष पृष्ठ 10 पर

कोल इंडिया...

का निर्माण होगा है। कोल इंडिया द्वारा वर्ष 2024 तक नए रेलवे साइडिंग निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि बीते वर्ष व वर्तमान में जारी कोरोना संक्रमण की वजह से जारी लॉकडाउन से रेलवे साइडिंग निर्माण की कार्य योजना की गति धीमी पड़ी है। जैसे ही कोरोना संक्रमण का खतरा हटेगा निर्माण कार्य में तेजी देखने को मिलेगी।

Date: 26-05-21
Publication: Hindustan Hindi
Edition: Ranchi

सड़क से कोयले की ढुलाई खत्म करने की ओर बढ़ रही कोल इंडिया

कोल वर्ल्ड

धनबाद | विशेष संवाददाता

कोल इंडिया चरणबद्ध ढंग से सड़क के माध्यम से कोयले की ढुलाई खत्म करने की योजना पर सक्रिय है। रोड की जगह रेल सहित अन्य माध्यम से कोयले की ढुलाई को तरजीह देगी। इसका फायदा वह होगा कि इससे ट्रैफिक पर दबाव कम होगा च हादसे में कमी आएगी। साथ ही कोयला क्षेत्र की हवा प्रदूषण मुक्त होगी।

यह खुलासा कोल इंडिया की ओर

बीसीसीएल में चुनौती ज्यादा

- कोयले में वर्चस्व को लेकर सक्रिय युगों में रोड मोड का आकर्षण। ज्यादातर लॉडिंग प्वाइंट ऐसे ही युगों के कब्जे में हैं, जहां से दबंग कोयले की ट्रांसपोर्टिंग को संवाहित करते हैं।
- रोड मोड में हजारों लॉडिंग मजदूरों को रोजगार मिला है। बीसीसीएल में इनकी बड़ी संख्या है। रोड मोड खत्म करने से मजदूरों के रोजगार का मुद्दा उठेगा।
- बीसीसीएल में चार मिलियन टन कोयला उत्पादन करने लायक एक भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए एफएमसी के तहत कन्वेंयर बेल्ट से ढुलाई बीसीसीएल में फिलहाल संभव नहीं है।

से जारी ईएसजी रिपोर्ट में की गई है। ईएसजी रिपोर्ट में कोल इंडिया ने

इंवायरमेंट (पर्यावरण), सोशल (सामाजिक) एवं गवर्नेंस संबंधी



पर्यावरण हितैषी पहल

04 मिलियन टन क्षमता वाले 35 कोल प्रोजेक्ट में कन्वेंयर बेल्ट से खदान से रैक तक कोयले की ट्रांसपोर्टिंग होगी। उक्त व्यवस्था से 151 मिलियन टन कोयले की ढुलाई हो सकेगी।

04 सौ पांच मिलियन टन कोयले की ढुलाई कन्वेंयर बेल्ट से करने का लक्ष्य तय किया है कोल इंडिया ने 2024 तक फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी योजना के तहत। यह कंपनी की मैकेनाइजेशन योजना का अहम हिस्सा है।

ढुलाई को बढ़ावा देने की पहल पहले से शुरू कर दी गई है। वर्तमान में 80 प्रतिशत कोयले की ढुलाई रेलमार्ग से होती है।

वहीं 20 प्रतिशत कोयले की ढुलाई सड़क मार्ग से हो रही है। इस 20% कोयले की ढुलाई को रेल सहित अन्य माध्यम से करना है। 2019-20 466.72 मिलियन टन कोयले की ढुलाई गैर-सड़क माध्यम से हुई। वहीं 115.20 मिलियन टन कोयले की ढुलाई रोड मोड में हुई थी। पर्यावरण सुरक्षा के लिए कोल इंडिया ने कई कदम उठाए हैं, जिनसे प्रदूषण को कम किया जा सकेगा।

Date: 27-05-21

Publication: The Hindu Business Line

Edition: Mumbai

CIL to tie up with mining equipment makers

As part of its revised business strategy, Coal India Ltd (CIL) has decided to join hands with reputed mining equipment manufacturers for expanding its existing large/medium mines and also to set up new ones. The new approach is to be followed to cut down its direct investment in heavy earth-moving equipment. The private sector's participation in the existing mines will be preferred if they are ready to bring in their contribution in the form mine-specific machinery and equipment.

Date: 31-05-21
Publication: The Hitavada
Edition: Jabalpur

Coal India retains output, offtake momentum in May

■ Coal India had recently said that the pandemic had impacted production

KOLKATA, May 30 (PTI)

DESPITE COVID-19 restrictions in several states, Coal India maintained its output and despatch momentum in May, the second month of the current fiscal, an official said.

The mining major is likely to report dry fuel production of around 41.7 million tonnes and offtake of nearly 55 million tonnes this month as against production of 41.43 million tonnes and sales of 40 million tonnes in the corresponding period last year, the official said.

In April, coal production stood at 41.9 million tonnes compared to 40.4 million tonnes in the year-ago period, recording a growth of 3.7 per cent.

Offtake stood at 54.1 million tonnes during the reporting month compared to 39.1 million tonnes in the corresponding period last year, registering a growth of 38.4 per cent.

Coal India Limited had recently said that the pandemic had impacted production on account of a large number of the company's employees across subsidiaries and contractors testing positive for coronavirus.

The Kolkata-based company i.e Coal India Limited commenced FY22 with a pithead stock of nearly 99 million tonnes. However, electricity demand had risen in recent months and the contribution of thermal power had improved, boosting

demand for coal. Thermal power meets 78 per cent of the country's power demand. However, there is apprehension that lockdowns may impact subsequent electricity demand from industry.